□□□□ □□□□□
स□□स्थ्य और परिवार कल्या□ □त्र□□□
स□□स्थ्य और परिवार कल्या□ □□□□□

□□ज□ □□□
□□□□□□□ प्रश्□ □ख□□: 290

15 □□□□, 2020 □□ □□□□□□□□□□□□□□प्रश्□ □□ □त्त□
□स□तालों म प्रवेश करने के लिए कोविड-19 प्र□□□-□त्र

290 श्री □□□□□□ □□□□

क्या स□□स्थ्य और परिवार कल्या□ मंत्री यह बताने को कृपा करगे कि:

(क) क्या सकरार के संज्ञान म ऐसी खबर आई ह कि सरकारी अस्पतालों म प्रवेश से पूव मरीजों को कोविड-19 को जांच को रिपोट लाने के लिए कहा जाता है ;
(ख) यदि हां, तो क्या गरीब लोगों को यह जांच रिपोट, लाने के लिए बाध्य करना उचित होगा, जिसको लागत लगभग 2400 रुपये है; और
(ग) क्या सरकार ऐसी प्रणाली बना सकती है जिसके माध्यम से अस्पतालों मे प्रवेश करने से पूव अस्पताल के द्वार पर ही सभी मरीजों को जांच को जा सके ?

□त□□
स□□स्थ्य और परिवार कल्या□ □□ज□ मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय है। भारत सरकार ने चल रहे आपातकालीन उपचारों के लिए कोविड टेस्ट कराने के लिए दबाव न बनाने हेतु राज्यों को एडवाइजरी जारी को है। यह एडवाइजरी सरकारी और प्राइवेट दोनों ही अस्पतालों पर लागू होती है।

सरकार के अधीन अस्पतालों म कोविड को जांच सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती है। सरकार सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) आंकड़ों के अनुसार लगभग 10.74 करोड़ निधन तथा उपेक्षित परिवारों (लगभग 50 करोड़ व्यक्तियों) को माध्यमिक एवं तृतीयक परिचया हेतु अस्पताल म भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) क्रियान्वित कर रही है। एबी-पीएमजेएवाई के लाभार्थियों को कोविड-19 को जांच एवं उपचार के लिए प्रभावी रूप से कवर करने के लिए 'कोविड-19 को जांच कराने' तथा 'कोविड-19 के उपचार' के लिए पैकेज को अधिसूचित किया जा चुका है।"

***